ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 211
ANSWERED ON 05.08.2022

RAILWAY ROUTES ANNOUNCED FOR PUNJAB

211 DR. ASHOK KUMAR MITTAL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of railway routes announced by Government during the last three years, especially for Punjab;

(b) the number of railway routes for which work has been completed;

(c) the number of railway routes for which work is pending along with the reasons therefor;

(d) whether Government has released the required funds by increasing the budget for the early completion of these routes, if so, the details thereof; and

(e) the steps taken by Government for demarcation of the proposed land for these projects and the details of amount of funds allocated under the project?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF STARRED QUESTION NO. 211 BY DR. ASHOK KUMAR MITTAL ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 05.08.2022 REGARDING RAILWAY ROUTES ANNOUNCED FOR PUNJAB

(a): The Railway projects are sanctioned/executed Zonal Railway wise and not State-wise as the Railways' projects may span across State boundaries. In the last three years i.e FY 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the current Financial year, 51 projects (10 New Line, 9 Gauge conversion and 32 Doubling) of total length 2178 km costing ₹29,734 crore have been sanctioned across Indian Railways which includes 2 Doubling projects of total length of 28 km costing ₹264 crore falling fully/partly in the State of Punjab.

(b) to (e): As on 01.04.2022, across Indian Railways, 452 Railway projects (183 New Line, 42 Gauge Conversion and 227 Doubling) of total length 49,323 Km, costing approx. ₹7.33 lakh crore are in different stages of planning/sanction/execution, out of which, 11,518 Km length has been commissioned and an expenditure of approx. ₹2.35 lakh crore has been incurred upto March, 2022.

Punjab:

As on 01.04.2022, 12 railway projects (06 New line and 06 Doubling) of total length 1,570 km, costing ₹23,810 crore, falling fully/partly in the state of Punjab are in different stages of planning/sanction/execution, out of which, 159 km length has been commissioned and an expenditure of ₹4,439 crore has been incurred upto March, 2022.

Railway infrastructure projects in the State of Punjab are covered under Northern Railway (NR) and North Western Railway (NWR) zone of Indian Railways. Zonal Railway wise details of Railway projects including cost, expenditure and outlay are made available in public domain on Indian Railways website i.e. www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways > Railway Board > About Indian Railways > Railway Board Directorates >Finance (Budget) >Rail Budget/Pink Book (Year)> Railway wise Works Machinery and Rolling Stock Programme.

Since 2014, there has been substantial increase in Budget allocation and commensurate commissioning of Infrastructure projects. Average Annual Budget allocation for Infrastructure projects & safety works, falling fully/ partly in the State of Punjab, during 2014-19 has been enhanced to ₹1,004 crore per year from ₹225 crore per year during 2009-14, which is 346% more than Average Annual Budget allocation

..P/2

during 2009-14. These allocations have been increased to ₹1,095 crore in Financial Year 2019-20 (387% more than the Average Annual Budget allocation of 2009-14), ₹1,565 crore in Financial Year 2020-21 (596% more than the Average Annual Budget allocation of 2009-14) and ₹2,262 crore in Financial Year 2021-22 (905% more than the Average Annual Budget allocation of 2009-14). For Financial Year 2022-23, highest ever budget outlay of ₹3,543 crore has been provided for these projects, which is 1475% more than the Average Annual Budget outlay of 2009-14 (₹225 crore per year).

Following important projects falling fully/partly in State of Punjab have been completed:-
Ambala - Chandigarh Doubling (45 Km), Mansa - Bhatinda Doubling (49 Km), Jallandhar-Pathankot-Jammu Doubling including important bridge over Ravi (211 Km), Nangal Dam – Daulatpur Chowk New Line (61 Km).

The completion of any Railway project(s) depends on various factors like quick land acquisition by State Government, forest clearance by officials of forest department, deposition of cost share by State Government in cost sharing projects, priority of projects, shifting of infringing utilities, statutory clearances from various authorities, geological and topographical conditions of area, law and order situation in the area of project(s) site, number of working months in a year for particular project site due to climatic conditions etc. and all these factors affect the completion time and cost of the project(s). With above constraints, every effort is being made to execute the project(s) expeditiously.

For Railway Projects, railways acquire land through district authorities of concerned State. Land acquisition and its demarcation is done by Revenue Authorities of State Government. Compensation for land acquired by the Railways is deposited with concerned State Government. Railways is closely and regularly following up with State Governments and concerned authorities for expeditious land acquisition/demarcation for Infrastructure projects.

******

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

05.08.2022 के

तारांकित प्रश्न सं. 211 का उत्तर

पंजाब के लिए रेल मार्गों की घोषणा

***211 डा. अशोक कुमार मित्तलः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से पंजाब के लिए घोषित रेल मार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने रेल मार्गों का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) ऐसे कितने रेल मार्ग हैं जिनके लिए कार्य लंबित है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन मार्गों को शीघ्र पूरा करने के लिए बजट में वृद्धि करके आवश्यक धनराशि निर्गत कर दी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि के सीमांकन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस परियोजना के तहत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

पंजाब के लिए रेल मार्गों की घोषणा संबंध में दिनांक 05.08.2022 को राज्य सभा में डॉ. अशोक कुमार मित्तल के तारांकित प्रश्न सं. 211 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क): रेल परियोजनाएं राज्य-वार नहीं बल्कि जोन-वार स्वीकृत/निष्पादित की जाती हैं क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। पिछले तीन वित्त वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21, 2021-22 और वर्तमान वित्त वर्ष में भारतीय रेल में 29,734 करोड़ रु. लागत की कुल 2,178 कि.मी. की 51 परियोजनाएं (10 नई लाइन, 9 आमान परिवर्तन और 32 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। इनमें पंजाब में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 264 करोड़ रु. की लागत वाली 28 कि.मी. कुल लंबाई की 2 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) से (ड.): 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में, कुल 49,323 किमी लंबाई की 452 रेल परियोजनाएं (183 नई लाइन, 42 आमान परिवर्तन और 227 दोहरीकरण) जिनकी लागत लगभग 7.33 लाख करोड़ रुपये है, योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 11,518 किमी लंबाई को पूरा कर दिया गया है और मार्च तक लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

पंजाब:

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, पंजाब में पूर्णत/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल 1570 किमी लंबाई की 12 रेल परियोजनाएं (6 नई लाइन और 6 दोहरीकरण) जिनकी लागत लगभग 23810 करोड़ रुपये है, योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 159 कि.मी. लंबाई को पूरा कर दिया गया है और मार्च, तक लगभग 4439 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

पंजाब राज्य में रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेलवे-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात www.indianrailways.gov.in>Ministry of Railways>Railway Board>About Indian Railways>Railway Board Directorates>Finance(Budget)> Pink Book (year)>Railways-wise Works, Machinery & Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

वर्ष 2014 से, रेल बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है और तदनुसार अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। 2014-19 के दौरान, पंजाब में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन, 2009-14 के दौरान, 225 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 1004 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 346% अधिक

है। इन आबंटनों को वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 1095 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 387% अधिक) और वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 1565 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 596% अधिक) कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, इन परियोजनाओं हेतु 2262 करोड़ रु. (2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आवंटन की तुलना में 905% अधिक) कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, इन परियोजनाओं हेतु अभी तक का सर्वाधिक 3543 करोड़ रु. का बजट परिव्यय मुहैया कराया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक परिव्यय की तुलना में 1475% अधिक है (225 करोड़ रु. प्रति वर्ष)।

पंजाब राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं:-
अंबाला-चंडीगढ़ दोहरीकरण (45 किमी.), मानसा-बठिंडा दोहरीकरण (49 किमी.), रावी नदी पर महत्वपूर्ण पुल सहित जालंधर-पठानकोट-जम्मू दोहरीकरण (211 किमी.) नंगल डैम-दौलतपुर चौक नई लाइन (61 किमी.)

रेल परियोजना (परियोजनाओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, लागत में हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्से को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परस्थितियों के कारण परियोजना (परियोजनाओं) विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं। इन सबके बावजूद परियोजना (परियोजनाओं) को शीघ्रता से पूरा करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

रेल परियोजनाओं के लिए, रेलवे संबंधित राज्य के जिला प्राधिकरणों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण और इसका सीमांकन राज्य सरकार के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। रेलवे द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा संबंधित राज्य सरकार के पास जमा किया जाता है। रेलवे द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए शीघ्र भूमि अधिग्रहण/सीमांकन के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाकर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

*****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: माननीय मंत्री जी, Dr. Ashok Kumar Mittal, ask the first supplementary.

डा. अशोक कुमार मित्तल : उपसभापति महोदय, पंजाब से कोलकाता को जोड़ने के लिए वर्ष 2007 में State Dedicated Freight Corridor की स्वीकृति दी गई थी, उसको पूरा करने की डेडलाइन वर्ष 2017 थी। आज 2022 हो गया है, पांच वर्ष अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह कम्प्लीट नहीं हुआ है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि इस देरी की वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो वृद्धि हुई है, जिसकी पुष्टि कैग ने भी की है, वह क्या है और इसको कब पूरा किया जाएगा?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : महोदय, प्रोजक्ट लेने के कई कारण होते हैं। एक तो यह कि जहां से लाइन जाती है, वहां ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माइक प्लीज़, सामने वाला माइक काम कर रहा है।

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : महोदय, यह डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर बहुत ही अच्छी योजना है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप माइक के सामने से फाइल हटा लेंगे, तो क्लियर आवाज़ आएगी।

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : महोदय, इसके लेट होने के कई कारण होते हैं। कई स्टेट्स में ज़मीन नहीं मिलती, कई जगह पर लोगों का ऐजिटेशन होता है और कई जगह पर पर्यावरण का विषय भी आ जाता है, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट्स लेट हो जाते हैं। अभी हम इसे लगभग पूरा करने जा रहे हैं।

डा. अशोक कुमार मित्तल : उपसभापति महोदय, 11 फरवरी को संसद में सरकार ने मंत्रालय के द्वारा कहा था कि दिल्ली-अमृतसर में बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अब यह सर्वे कम्प्लीट हो चुका है? आप इस प्रोजेक्ट को कब शुरू करने जा रहे हैं और उसकी समय सीमा क्या रहेगी, ताकि पंजाब को सरकार की तरफ से एक अच्छा उपहार दिया जा सके?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : महोदय, माननीय सदस्य जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके सर्वे के आदेश हुए थे, लेकिन अभी तक कोई डीपीआर नहीं बनी और सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

डा. अनिल अग्रवाल : उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन एनसीआर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, वहां पर सिविक फैसिलिटीज़ काफी कम हैं। पूर्व में भी घोषणा की जा चुकी है कि इस स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन अभी तक वहां कुछ काम नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन को कब तक अपग्रेड किया जाएगा और कब तक सिविक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : महोदय, हम इस देश में कुछ स्टेशन डेवपलमेंट के प्रोग्राम ले चुके हैं, कुछ अदर स्टेशंस के काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन गाज़ियाबाद स्टेशन के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, इस संबंध में मैं उनसे मिलूंगा या वे मेरे ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, it is slightly a different question but it comes under this only, the Railway and hon. Minister is ready with the answer. I would ask a straight question to the hon. Minister. Since it involves the prestige and integrity of two Cabinet Ministers, including Shri Piyush Goyal and Shri Ashwini Vaishnaw, will the hon. Railway Minister scrap the Office Memorandum dated 30.5.2022, thereby, deciding to do away with the Nemom Terminal Project in Kerala?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY; THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI PIYUSH GOYA)L: Sir, if I can...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This question... ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... No, no, please. ...*(Interruptions)*... One minute. ...*(Interruptions)*... ...*(Interruptions)*... I will just come. ...*(Interruptions)*... I will come. ...*(Interruptions)*... Yes, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, he is a friend of mine. I just want to ask him a small thing. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI PIYUSH GOYAL: My esteemed colleague and good friend, normally, asks straight questions and he sometimes asks googly questions. Today, he has asked a straight question!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: John Brittas*ji*, the question relates to railway routes announced for Punjab and not for Kerala. So, please*...(Interruptions)...* No, no. Now Shri Raghav Chadha. Raghav Chadha*ji*, please ask your question.

श्री राघव चड्ढा : उपसभापति महोदय, सितम्बर, 2021 में भारत सरकार ने बहुत धूमधाम से एक घोषणा की थी कि एक गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन देश भर में चलाई जाएगी, जिस ट्रेन के माध्यम से 11 दिन के भीतर इस देश के कई बड़े गुरुद्वारा साहिब को जोड़ा जाएगा और संगत 11 दिन के अंदर अमृतसर से शुरू होने वाली उस यात्रा को अमृतसर में समाप्त कर पाएगी। सिख संगत ने इसका स्वागत भी किया था। सर, दुख की बात यह है कि रिपोर्ट से यह मालूम हो रहा है कि शायद उस प्रोजेक्ट पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन की जो अनांउसमेंट की थी, उस अनांउसमेंट के संदर्भ में अभी सरकार की ओर से क्या प्रोग्रेस है?

रेल मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव): उपसभापति महोदय, सांसद महोदय ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। उसका नाम गुरुकृपा था। गुरुकृपा सर्किट की जो बात हुई थी, तो बेसिकली माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विज़न में भारत गौरव का एक नयी ट्रेन का कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसमें भारत की संस्कृति से जुड़े जितने भी आस्पैक्ट्स हैं, उनको दिखाने का, उनको एक्सपीरियंस करने का रेलवे एक बहुत बड़ा माध्यम बने। वह स्कीम बहुत अच्छी तरह से आगे चल रही है। उसमें पहली ट्रेन रामायण एक्सप्रेस आई। आप सबने रामायण सर्किट को देखा होगा। उसका बहुत अच्छा रेस्पांस मिला है। उसके बाद दिव्य काशी यात्रा ट्रेन आई है, शिरडी ट्रेन आई है। इस पूरे प्रोग्राम में हमारे जितने भी स्टेकहोल्डर्स हैं, राज्य सरकारें जुड़ें, टूर ऑपरेट्र्स जुड़ें, स्ट्रेटस की जो टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन्स हैं, वे सभी जुड़ें। अभी हाल ही में कर्णाटक स्टेट कॉरपोरेशन ने...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, the question is on Guru Kripa. The hon. Member has asked a straight question. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* He is replying. *...(Interruptions)...*

SHRI ASHWINI VAISHNAW: I am giving a very straight answer. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: No, you are not giving*...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please. *...(Interruptions)...* प्लीज़, सीट पर बैठकर न बोलें।...(व्यवधान)...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: I am giving a very straight answer. ...*(Interruptions)*... His question is straight and I am giving a very straight answer. ...*(Interruptions)*... उसी सीरीज़ में सबसे important चीज़ यह है कि यह संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। उसमें हम अपने सरकारी तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं। जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे गुरुद्वारे से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग आगे आएं और वे कॉन्सेप्ट को ढंग से डेवलप करें। उनके साथ ऑलरेडी बातचीत भी चल रही है, दिल्ली में भी बात चल रही है, अमृतसर, नान्देड़ साहब में भी बात चल रही है। इन सबसे ऑलरेडी बातचीत चल रही है। जैसे ही कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज़ करेंगे, तभी वह ट्रेन स्टार्ट होगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Question Nos. 212 and 218 to be taken together.